



गत वर्ष पेरिस के लुव्र म्यूजियम के स्टाफ ने एक गुप्त कार्यवाही की योजना बनायी शुरु की, जिसका मिशन था, रूस के हमलों के बीच यूक्रेन से 16 कलाकृतियों को बाहर निकालना। ये कलाकृतियाँ मूल रूप से क्लैव के बगदर वरवारा खानेको म्यूजियम में रखी थीं। म्यूजियम ने रूस के आक्रमण के शुरु में ही अपना समस्त आर्ट कलेक्शन छुपा दिया था। फिर भी, अक्टूबर महीने में एक मिसाइल हमले में यह बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई और यूक्रेन के अधिकारियों को स्पष्ट हो गया कि देश की सांस्कृतिक विरासत खतरों में है। इसके बाद, एक गुप्त काफिले के माध्यम से, पोलैंड और जर्मनी होते हुए कलाकृतियों फ्रांस पहुँची। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन नाजुक कलाकृतियों को विशेष रूप से बनाए गए एयर कण्टेनर में रखा गया। अब लुव्र जाने वाले लोग, यूक्रेन से सुरक्षित लाई गई 16 में से 5 कलाकृतियों को, "द ओरिजिनल ऑफ द सेक्रेड इमेज" नाम की एक नई एक्जीबिशन में देख सकते हैं। बाकी ग्यारह कलाकृतियों में से नौ को वर्तमान में, पेरिस से करीब 100 मील दूर शहर, "लिलेवॉ" के लुव्र कन्जर्वेशन सेंटर में रखा गया है और दो कलाकृतियों का अभी वैज्ञानिक विश्लेषण होना बाकी है। एक्जीबिशन खत्म होने के बाद लुव्र इन कलाकृतियों का गहराई से विश्लेषण करेगा और जब युद्ध समाप्त होगा तो कलाकृतियों खानेको म्यूजियम को लौटा दी जाएंगी। ऊपर दिए चित्र में यूक्रेन से आई जो कलाकृति नजर आ रही है उसमें सेंट सरजिअस व सेंट बैकवस को दिखाया गया है।

खड़गे की अनुपस्थिति के कारण राजस्थान के बारे में आयोजित बैठक रद्द हुई

खड़गे कर्नाटक चले गये थे तथा देर शाम को ही दिल्ली लौटे

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कर्नाटक से शाम को दिल्ली लौटे आए। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की आज होने वाली बैठक खड़गे की अनुपस्थिति की वजह से रद्द करनी पड़ी। उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि बैठक अगले कुछ दिनों में और ज्यादा से ज्यादा इस सप्ताह के अंत तक हो सकती है और राजस्थान के संकट का समाधान किया जा सकता है भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें सहयोग करें या नहीं।

सचिन पायलट आज दिल्ली आए थे और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डोटारसा भी दिल्ली आए थे।

समझा जाता है कि गहलोत का लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे का संरक्षण प्राप्त है, जबकि राहुल गांधी ने

■ चर्चा है कि, गहलोत को खड़गे का प्रश्रय व संरक्षण प्राप्त है।

■ बहरहाल, राहुल गांधी राजस्थान का संकट सुलझाने के बारे में दृढ़ हैं तथा के.सी. वेणु गोपाल को आदेश दे रखा है कि, राजस्थान का मसला जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर में सुलझाना चाहिये, गहलोत की सहमति व सहयोग हो या न हो।

■ कोटा में वसुंधरा राजे द्वारा आयोजित विशाल रैली ने भाजपा व कांग्रेस दोनों को काफी हिला दिया है। भाजपा हाई कमान वसुंधरा राजे को ज्यादा पसंद नहीं करता और उन्हें मु.मंत्री बनाने में हाई कमान की कोई रुचि नहीं है, पर, बात शायद हाई कमान के हाथ से निकल चुकी है।

■ दूसरी ओर वसुंधरा राजे की "लोकप्रियता" देखते हुए, कांग्रेस के लिये बहुत जरूरी है कि, पार्टी को चुनाव के लिये तैयार करे, गहलोत-पायलट मतभेदों को सुलझा कर।

के.सी. वेणुगोपाल को निर्देश दिया है कि राजस्थान के विवाद का शीघ्रतरी समाधान किया जाए।

अब तक अनिर्णयग्रस्त व ढिलाई

बत रहा कांग्रेस नेतृत्व संकट समाधान के लिए इतनी शीघ्रता इसलिए कर रहा है क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे का

नेतृत्व उभर रहा है, उन्होंने कोटा में एक बड़ी रैली की जिसने कांग्रेस ही नहीं भाजपा की भी आंखें खोल दी है।

वसुंधरा राजे राजस्थान की सबसे करिश्माई नेता है तथा थोड़ी खींचती है

और भाजपा नेता खासकर मोदी शाह ना तो राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं

और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में

देखना चाहते हैं।

लेकिन हालात भाजपा नेतृत्व के नियंत्रण से बाहर है।

वसुंधरा के सामने आने से कांग्रेस को अपने संगठन को व्यवस्थित करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी।

सी.डब्ल्यू.सी. में पायलट को सीट ऑफर?

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। कांग्रेस ने सोमवार को संगठनात्मक मसले सुलझा लिए जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन प्रमुख है, जिसकी जिम्मेवारी गत वर्ष अक्टूबर में मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही

■ कांग्रेसी सूत्रों के हवाले से खबर है कि, सचिन पायलट को दिल्ली में एक सीनियर पोस्ट ऑफर की गई है। एक सप्ताह में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी हो जाएगी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

उन्हें सौंपी दी गई थी।

राजस्थान के बागी नेता सचिन पायलट को दिल्ली में वरिष्ठ पद और सी.डब्ल्यू.सी. में सीट की पेशकश की गई है। सी.डब्ल्यू.सी. कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णयकारी समिति है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि फेरबदल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने चार घंटे मंत्री परिषद की बैठक ली

मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन पर चर्चा से लगा कि, लगभग दस मंत्रियों को "ड्रॉप" कर संगठन व चुनाव के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी दी जायेगी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार की रात को चार घंटे तक अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग ली तथा ऐसी अटकले चर्चा में रही कि 10 मंत्री या तो भाजपा संगठन में भेज दिये गये हैं या फिर उन राज्यों में पहुंचा दिये गये हैं, जहाँ विधानसभा चुनाव इसी साल, अगले साल अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले, होने हैं।

एक अटकल यह भी है कि नेशनलिस्ट पार्टी के अजीत पवार, जिन्होंने तीसरी बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, को पदोन्नति देकर, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तथा 59 वर्षीय वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना) 52 वर्षीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस तथा एन.सी.पी. नेता प्रफुल्ल पटेल केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किये जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि अजीत पवार 1 जुलाई

■ महाराष्ट्र के मु.मंत्री एकनाथ शिंदे, उप मु.मंत्री देवेंद्र फडनवीस व एन.सी.पी. के प्रफुल्ल पटेल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में स्थान पा सकते हैं।

■ इस आशंका पर भी चर्चा हुई कि, अजीत पवार व उनके साथ आये व मंत्री बने एन.सी.पी. के नेताओं की संख्या पर्याप्त नहीं, दल-बदल कानून के दायरे में आने से बचने के लिये।

तक विपक्ष के नेता थे।

इस जमीनी हकीकत का आँकलन करने के बाद कि अजीत तथा आठ अन्य लोग, जिन्होंने मंत्रीपद की शपथ ली थी, के पास उतना संख्या बल नहीं है, जो पद पर बने रहने के लिये जरूरी है क्योंकि इन्हें कम से कम 36 विधायक चाहिये, क्योंकि एन.सी.पी. विधायक संख्या 53 है, एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार ने राज्य के एन.सी.अध्यक्ष जयन्त पाटिल से कहा कि वे दलबदल-विरोधी कानून के अन्तर्गत, इन सभी 9 नेताओं को डिसक्वालिफिकेशन का नोटिस दे दें।

अजीत ने पलटवार करते हुये, उन्हें एन.सी.पी. से निकालने के पत्र के मिलते ही, पाटिल को उनके पद से हटा दिया। सूत्रों ने यहाँ बताया कि जब अजीत ने यह देखा कि उनके समर्थन में आये विधायकों ने शरद पवार की ओर लौटना शुरु कर दिया है तो उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से समझौता करने की कोशिश की। अजीत के शपथ लेने वाले दिन, उनके साथ 13 विधायक थे, लेकिन अब उनकी संख्या 10 ही रह गई है, जो कि अजीत की डिसक्वालिफिकेशन का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में भी महाराष्ट्र की भांति नीतीश की पार्टी में विभाजन संभव?

भाजपा के सुशील मोदी ने विभाजन की संभावना को बल देते हुए कहा, कई जद (यू) विधायक, नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं हैं तथा उन्होंने भाजपा से सम्पर्क साधा है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) में तोड़-फोड़ करके दिग्गज मराठा नेता शरद पवार को जबर्दस्त धक्का पहुँचाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी यही खेल खेलने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में कई जे.डी (यू.) विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. में वापसी की बात को खारिज करते हुये, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि उन्हें 17 साल तक जैसे बर्दाश्त किया गया लेकिन अब आगे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बिहार की राजनैतिक अस्तव्यवस्था के चलते भाजपा ने

नीतीश कुमार को 17 साल तक बर्दाश्त किया लेकिन एन.डी.ए. में वे अब आगे स्वीकार्य नहीं।

सुशील मोदी ने यहाँ पत्रकारों को बताया कि जेडी (यू.) नेता नीतीश कुमार पर नाराज हैं तथा उनमें से कई लोगों ने भाजपा से सम्पर्क किया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश एन.डी.ए. में आना चाहेंगे भी तो भी उन्हें आने नहीं दिया जायेगा।

सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री को एन.डी.ए. में स्वीकार किये जाने के बिन्दु पर कहा: "भाजपा ने नीतीश कुमार को 17 साल तक बर्दाश्त किया।" --बिहार को राजनैतिक अव्यवस्था पर चलेते हुये मोदी ने कहा कि 17 साल में नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को कभी भी समय नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे एक साल तक प्रतीक्षा करने के बाद, वे उन्हें

30 मिनट दे रहे हैं।

मोदी के अनुसार, जेडी (यू.) में विद्रोह की स्थिति है क्योंकि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई (2024 के लोकसभा चुनाव) का नेता स्वीकार कर लिया है तथा लालू प्रसाद के बेटे एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। उन्होंने कहा, "(जेडी (यू.) का) कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।" वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उन्होंने कहा कि जेडी (यू.) 8-10 सीटों से ज्यादा शायद ही जीत सके, जिसके कारण पार्टी सांसद एवं विधायक आशंकित है कि जेडी (यू.) में उनका भविष्य अच्छा नहीं है।

इस बीच, सुशील मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विपक्ष की बैठक अब 17-18 जून को बँगलूरु में होगी'

कांग्रेस के महासचिव वेणु गोपाल ने ट्विटर पर यह घोषणा की

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। कांग्रेस ने आज घोषणा की कि विपक्षी दलों की अगली बैठक बँगलूरु में 17 और 18 जुलाई को होगी। पार्टी ने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन के "मुंबई ऑपरेशन्स" ने भाजपा को हराने के उसके इरादों को और मजबूत का दिया है। यह बैठक 20 जुलाई से आरंभ होने वाले संसद के सत्र की पूर्व संख्या पर होगी और यह भाजपा को स्पष्ट संदेश है कि विपक्षी एकता को तोड़ने के उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने विपक्ष की बैठक की तिथियाँ ट्विटर पर घोषित की और कहा, "हम फासिस्टों और अलोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष हमारे संकल्प

पर अटल है।" वेणु गोपाल ने कहा, "पटना में सभी विपक्षी दलों की सफल बैठक के बाद अगली बैठक बँगलूरु में 17 एवं 18 जुलाई 2023 को होगी। हम फासिस्टों और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के दृष्टिकोण पर अडिग हैं।"

कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम मेघा ने एन.सी.पी. के अजीत पवार और आठ अन्य नेताओं को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल करने को लेकर भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, "कल जब भाजपा वॉशिंग मशीन की मुंबई में अपने आई.सी.ई. (इन्कम टैक्स, सी.बी.आई., ई.डी.) डिटेक्ट के साथ दोबारा शुरू हुई तो भाजपा के इशारे पर विपक्षी एकता को श्रद्धांजलियाँ दी जाने

■ भतीजे अजीत पवार की बगावत से प्रारंभ में तो शरद पवार कुछ हतप्रभ से लगे, पर फिर बाद में, जमीन से पार्टी पुनः खड़ी करने की बात कही और इस मकसद से पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकल पड़े।

■ पुणे से कराई पहुंचे शरद पवार के स्वागत में हजारों लोग इकट्ठे हुए। स्थानीय विधायकों के अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी स्वागत में मौजूद थे, विपक्ष की एकता का मैसेज देने के लिये।

लगाँ लेंकिन शोक संदेश लिखने वालों को निराशा होगी कि 23 जून को पटना में जिन पार्टियों की बैठक हुई थी वे 17-18 जुलाई को फिर मिलेगी। रमेश ने ट्विटर पर कहा, "मुंबई ऑपरेशन्स" ने विपक्ष के इरादे और मजबूत कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुटकी लेते हुए रमेश ने "मोदी वॉशिंग पाउडर"

की एक फोटो टैग करत हुए लिखा, "सारे दाग चुटकियों में धुलो!" राज्यसभा में तुणलु कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने वेणु गोपाल के ट्वीट को टैग करत हुए लिखा, "बँगलूरु सम्मेलना सब एक के लिए, एक सबके लिए!" इससे पहले एन.सी.पी. के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि विपक्ष की

अगली बैठक बँगलूरु में 13-14 जुलाई को होगी। वे तिथियाँ कुछ राज्यों में विधानसभा सत्रों से टकरा रही थीं। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी।

हालांकि रविवार को लगे झटके से शरद पवार को भारी शर्मिंदगी हुई है क्योंकि भाजपा के विरुद्ध महागठबंधन बनाने के पीछे उन्हीं का हाथ है, लेकिन भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र के ये वरिष्ठ नेता प्रतिद्वंद्वियों का दौंव पलटने में माहिर हैं। भगवा पार्टी के कर्ता-धर्ता और उसके हथियार जैसे सी.बी.आई., ई.डी. और आयकर आदि को जनता के साथ पवार के सम्पर्क का अंदाज नहीं है। शरद पवार ने आज शक्ति प्रदर्शन किया और भाजपा पर विपक्षी पार्टियों को नष्ट करने का आरोप लगाया। पवार ने एन.सी.पी. के पुनरूत्थान की भी

शपथ ली। अपने भतीजे के विद्रोह से राजनैतिक शर्मिंदगी झेलने के अगले दिन ही उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, जब वे अपने संरक्षक और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण के सतारा स्थित स्मारक पर गुरु पूर्णिमा को श्रद्धांजलि देने गए थे। अपने समर्थकों से भावपूर्ण अपील करते हुए उन्होंने कहा कि, "आज महाराष्ट्र और देश में कुछ गुटों द्वारा धर्म और जाति के नाम पर समाज में दरार डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बागी वापस आ सकते हैं लेकिन इसकी समय सीमा है। कल 82 वर्षीय नेता ने दावा किया था कि वे अपने भतीजे अजीत पवार के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई काया पलट के साथ सुप्रीम कोर्ट खुला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 जुलाई। ग्रीष्मवकाश के बाद, जब सर्वाधिक न्यायालय सोमवार को फिर से खुला तो उसका

■ सोमवार को ग्रीष्मवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट पुनः खुला। डिजिटल स्क्रीन, लायब्रेरी और वाय-फाय कनेक्टिविटी जैसा आधुनिक सुविधाएं आने से किताबों और फाइलों की अलमारियाँ हटा दी गई हैं।

काया पलट हो चुका था, अदालत के कक्षों से किताबों की अलमारियाँ हटा दी गई हैं तथा इस प्रकार, कक्षों में ज्यादा जगह निकल आई है, तथा वकीलों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विज्ञापनों के लिए पैसा है तो सड़क निर्माण के लिए क्यों नहीं'

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार पर बरसा क्योंकि वह रिजलन रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना

■ सुप्रीम कोर्ट ने रिजलन रैपिड ट्रांजिटेड सिस्टम के लिए फंड नहीं देने पर दिल्ली की आप सरकार से सवाल किया और तीन साल के विज्ञापन खर्च की जानकारी मांगी।

शराब व्यापारी महेन्द्रू को अंतरिम जमानत

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब व्यापारी समीर महेन्द्रू

■ सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी समीर महेन्द्रू को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की तथा जमानत के विरुद्ध दायर की गई ई.डी. की याचिका को खारिज कर दिया।

को दी गई 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की अपील खारिज कर दी। जमानत में कई प्रतिबंध (शेष अंतिम पृष्ठ पर)